NITIN SIR CLASSES

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

दैनिक समाचार विश्लेषण

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Tuesday, 16 Sep, 2025

Edition : InternationalTable of Contents

Page 01 & 05 **Syllabus :GS 2 : Indian Polity/ Prelims**	सुप्रीमकोर्टने 'वक्फ बाय यूजर' को वैधानिक मान्यता से मुक्त करने के कदम का समर्थन किया
Page 08 **Syllabus :Essay & GS 1, 2 & 3 : Social issues, Indian Polity & Indian Economy / Prelims**	भारतकीआर्थिकमहत्वाकांक्षाओं के लिए बेहतर लिंग डेटा की आवश्यकता है
Page 09 **Syllabus :GS 2 : Social Justice / Prelims**	मानसिकस्वास्थ्यकोसही मानने के लिए अदालत की मंजूरी
Page 10 **Syllabus :GS 2 : Indian Polity / Prelims**	जातिगतअपराधमेंअग्रिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट
Page 12 **Syllabus :GS 3 : Indian Economy/ Prelims**	'एआईकेनेतृत्ववाली क्षमताएं 8% जीडीपी विकास लक्ष्य में योगदान कर सकती हैं'
Page 08 : Editorial Analysis **Syllabus :GS 3 : Science and Technology**	भारतकेखरीदसुधारों के साथ नवाचार को बढ़ावा देना

Page 01 &05 :GS 2 : Indian Polity / Prelims

सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने हाल ही में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें धार्मिक अधिकारों, संपत्ति के अधिकारों और वक्फ प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने में राज्य के हित को संतुलित किया गया है। जबकि अदालत ने अधिनियम की व्यापक वैधता को बरकरार रखा, इसने कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी, जो प्रथम दृष्टया मनमाने पाए गए - विशेष रूप से वे जो कार्यपालिका को अनियंत्रित शक्तियां देते थे और संपत्ति के शीर्षक के न्यायिक निर्धारण को कमजोर करते थे। यह मामला शक्तियों के पृथक्करण, अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा और धार्मिक बंदोबस्ती में जवाबदेही के संवैधानिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है।

फैसले की मुख्य विशेषताएं

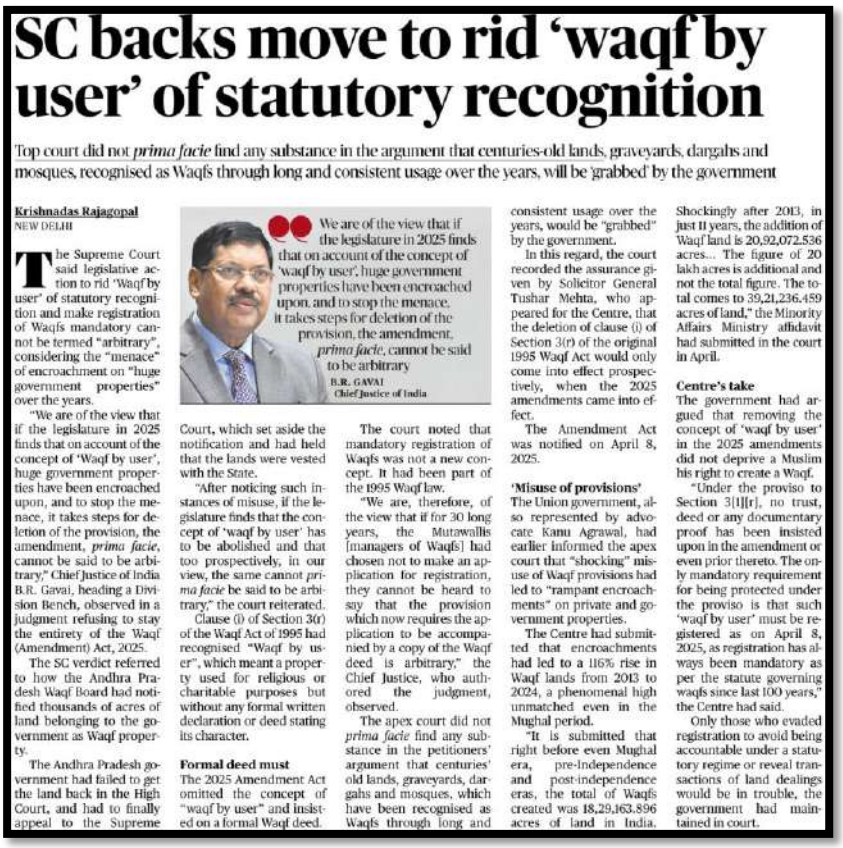

SC backs move to rid 'waqf by user' of statutory recognition

Top court did not *prima facie* find any substance in the argument that centuries-old lands, graveyards, dargahs and mosques, recognised as Waqfs through long and consistent usage over the years, will be 'grabbed' by the government

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

The Supreme Court said legislative action to rid 'Waqf by user' of statutory recognition and make registration of Waqfs mandatory cannot be termed "arbitrary", considering the "menace" of encroachment on "huge government properties" over the years.

"We are of the view that if the legislature in 2025 finds that on account of the concept of 'Waqf by user', huge government properties have been encroached upon, and to stop the menace, it takes steps for deletion of the provision, the amendment, *prima facie*, cannot be said to be arbitrary," Chief Justice of India B.R. Gavai, heading a Division Bench, observed in a judgment refusing to stay the entirety of the Waqf (Amendment) Act, 2025.

The SC verdict referred to how the Andhra Pradesh Waqf Board had notified thousands of acres of land belonging to the government as Waqf property.

The Andhra Pradesh government had failed to get the land back in the High Court, and had to finally appeal to the Supreme Court, which set aside the notification and had held that the lands were vested with the State.

"After noticing such instances of misuse, if the legislature finds that the concept of 'waqf by user' has to be abolished and that too prospectively, in our view, the same cannot *prima facie* be said to be arbitrary," the court reiterated.

Clause (i) of Section 3(r) of the Waqf Act of 1995 had recognised "Waqf by user", which meant a property used for religious or charitable purposes but without any formal written declaration or deed stating its character.

Formal deed must

The 2025 Amendment Act omitted the concept of "waqf by user" and insisted on a formal Waqf deed.

The court noted that mandatory registration of Waqfs was not a new concept. It had been part of the 1995 Waqf law.

"We are, therefore, of the view that if for 30 long years, the Mutawallis [managers of Waqfs] had chosen not to make an application for registration, they cannot be heard to say that the provision which now requires the application to be accompanied by a copy of the Waqf deed is arbitrary," the Chief Justice, who authored the judgment, observed.

The apex court did not *prima facie* find any substance in the petitioners' argument that centuries' old lands, graveyards, dargahs and mosques, which have been recognised as Waqfs through long and consistent usage over the years, would be "grabbed" by the government.

In this regard, the court recorded the assurance given by Solicitor General Tushar Mehta, who appeared for the Centre, that the deletion of clause (i) of Section 3(r) of the original 1995 Waqf Act would only come into effect prospectively, when the 2025 amendments came into effect.

The Amendment Act was notified on April 8, 2025.

'Misuse of provisions'

The Union government, also represented by advocate Kanu Agrawal, had earlier informed the apex court that "shocking" misuse of Waqf provisions had led to "rampant encroachments" on private and government properties.

The Centre had submitted that encroachments had led to a 116% rise in Waqf lands from 2013 to 2024, a phenomenal high unmatched even in the Mughal period.

"It is submitted that right before even Mughal era, pre-Independence and post-independence eras, the total of Waqfs created was 18,29,163.896 acres of land in India. Shockingly after 2013, in just 11 years, the addition of Waqf land is 20,92,072.536 acres... The figure of 20 lakh acres is additional and not the total figure. The total comes to 39,21,236.459 acres of land," the Minority Affairs Ministry affidavit had submitted in the court in April.

Centre's take

The government had argued that removing the concept of 'waqf by user' in the 2025 amendments did not deprive a Muslim his right to create a Waqf.

"Under the proviso to Section 3[1][r], no trust, deed or any documentary proof has been insisted upon in the amendment or even prior thereto. The only mandatory requirement for being protected under the proviso is that such 'waqf by user' must be registered as on April 8, 2025, as registration has always been mandatory as per the statute governing waqfs since last 100 years," the Centre had said.

Only those who evaded registration to avoid being accountable under a statutory regime or reveal transactions of land dealings would be in trouble, the government had maintained in court.

We are of the view that if the legislature in 2025 finds that on account of the concept of 'waqf by user', huge government properties have been encroached upon, and to stop the menace, it takes steps for deletion of the provision, the amendment, *prima facie*, cannot be said to be arbitrary

B.R. GAVAI
Chief Justice of India

1. **संवैधानिकता की धारणा** – सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि एक संसदीय कानून को तब तक वैध माना जाता है जब तक कि स्पष्ट रूप से असंवैधानिक न हो।
2. **रुके हुए प्रावधान:**
   - इस्लाम का पालन करने का 5 साल का सबूत: सुप्रीम कोर्ट ने इस विचार को वैध माना लेकिन इस पर रोक लगा दी क्योंकि कोई स्पष्ट तंत्र मौजूद नहीं है।
   - धारा 3 सी परंतुक: केवल संदेह पर वक्फ को सरकारी संपत्ति घोषित करना "पूरी तरह से असंवैधानिक" माना गया। केवल न्यायपालिका ही स्वामित्व तय कर सकती है, कार्यकारी अधिकारी नहीं।
   - राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव: कार्यकारी एकतरफा वक्फ बोर्ड और राजस्व रिकॉर्ड को बदल नहीं सकता है।
3. **वक्फ परिषद और बोर्ड:**
   - केंद्रीय वक्फ परिषद → 22 में से अधिकतम 4 गैर-मुस्लिम हैं।
   - राज्य वक्फ बोर्ड में 11 में से अधिकतम 3 गैर-मुस्लिम →।
   - राज्य वक्फ बोर्ड के सीईओ → अधिमानतः एक मुस्लिम हैं।
4. **अनिवार्य पंजीकरण**:
   - लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता (1923 से, 1995 अधिनियम के तहत जारी रही)।
   - सुप्रीम कोर्ट ने 2025 के संशोधनों में वक्फ डीड की आवश्यकता को बरकरार रखा।

5. **"उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ" का उन्मूलन**:
    - अदालत ने "उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ" (बिना विलेख के वक्फ के रूप में उपयोग की जाने वाली संपत्ति) की मान्यता को हटाने वाले संशोधन को बरकरार रखा।
    - सरकार ने राज्य की भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण का हवाला देते हुए इसे उचित ठहराया, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश का मामला।
    - सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर सहमति जताई कि अगर इसे संभावित रूप से लागू किया जाता है तो इसे मनमाना नहीं कहा जा सकता है।

स्थैतिक संदर्भ

- **वक्फ क्या है?** धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए एक मुस्लिम द्वारा चल/अचल संपत्ति का स्थायी समर्पण।
- **वक्फ अधिनियम, 1995**:
    - राज्य स्तरीय प्रबंधन के लिए वक्फ बोर्ड की स्थापना की।
    - उपयोगकर्ता द्वारा पहचाना गया वक्फ।
    - पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया लेकिन विलेख की आवश्यकता नहीं थी।
- **समस्याएं**:
    - सरकारी/निजी भूमि पर अतिक्रमण।
    - पंजीकरण और प्रबंधन में जवाबदेही का अभाव।
    - रिपोर्ट: भारत में 8 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां, ~6 लाख अपंजीकृत (सच्चर समिति, 2006 के अनुसार)।
- **शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत**:
    - मालिकाना हक के विवाद न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं, कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं।

वर्तमान संदर्भ (अब प्रासंगिक क्यों?)

- **वक्फ भूमि में भारी वृद्धि: वक्फ भूमि** → सरकारी हलफनामे में 2013-2024 के बीच 116% की वृद्धि हुई (~18.3 लाख एकड़ से ~39.2 लाख एकड़ तक)।
- **दुरुपयोग के आरोप:** सरकार ने तर्क दिया कि कई दावे धोखाधड़ी वाले थे, जिससे अतिक्रमण पैदा हुआ।
- **राजनीतिक और अल्पसंख्यक संवेदनशीलता**:
    - विपक्ष संशोधनों को मुस्लिम संस्थानों को निशाना बनाने के रूप में देखता है।
    - सरकार संपत्ति सुधार के रूप में बचाव करती है, धार्मिक हस्तक्षेप के रूप में नहीं।
- **सुप्रीम कोर्ट की भूमिका**: एक संवैधानिक संतुलन-रक्षक के रूप में कार्य करना → अल्पसंख्यक अधिकारों और सार्वजनिक संपत्ति के हितों दोनों की रक्षा करना।

निष्कर्ष

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला न्यायिक संतुलन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है - वक्फ शासन में सुधार करने के लिए संसद के इरादे को बरकरार रखते हुए संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाले मनमाने प्रावधानों को खत्म करना। आगे बढ़ते हुए, यह निर्णय भारत में धार्मिक बंदोबस्ती को विनियमित करने के तरीके को नया आकार दे सकता है, यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक संपत्ति और कानून के शासन से समझौता किए बिना अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षित किया जाए।

दैनिक समाचार विश्लेषण

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारत में वक्फ विनियमन के लिए सबसे अधिक सीधे प्रासंगिक है?

1. अनुच्छेद 25 – धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

2. अनुच्छेद 26 – धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार

3. अनुच्छेद 29 – अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकारों का संरक्षण

4. अनुच्छेद 300A – संपत्ति का अधिकार

सही उत्तर का चयन कीजिए:

a) केवल 1, 2 और 3

b) केवल 1, 3 और 4

c) 1, 2, 3 और 4

d) केवल 2 और 4

उत्तर: (c)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: सरकार ने सार्वजनिक भूमि के बड़े पैमाने पर अतिक्रमण का हवाला देते हुए "उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ" को समाप्त करने को उचित ठहराया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इस तरह के कदम से धार्मिक बंदोबस्ती में जवाबदेही सुनिश्चित होती है? अपने उत्तर की पुष्टि करें। **(250 शब्द)**

Page 08 :Essay&GS 1, 2 & 3 : Social issues, Indian Polity & Indian Economy / Prelims

निबंध उद्धरण: "महिला सशक्तिकरण केवल एक सामाजिक न्याय लक्ष्य नहीं है, बल्कि India@2047 के लिए एक आर्थिक आवश्यकता है।

2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की भारत की आकांक्षा समावेशी विकास पर निर्भर करती है। हालाँकि, सकल घरेलू उत्पाद में महिलाओं का योगदान केवल 18% और कार्यबल के बाहर लगभग 196 मिलियन रोजगार योग्य महिलाओं के साथ, भागीदारी में लिंग अंतर एक महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में महिला आर्थिक सशक्तिकरण (WEE) सूचकांक का हालिया लॉन्च शासन और डेटा सिस्टम में लिंग लेंस को शामिल करके इस चुनौती को संबोधित करने में एक अभिनव कदम प्रदान करता है।

India's economic ambitions need better gender data

Pooja Sharma Goyal

is the Founding CEO of The Udaiti Foundation

Vivek Kumar

is Program Lead, The Udaiti Foundation

Women contribute just 18% to India's GDP today, but continuing with business-as-usual means that trillions of dollars will be left on the table. India's aspiration to become a $30 trillion economy by 2047 rests on a simple truth: inclusive growth cannot happen if half its population remains invisible in the data that drive policy and investment. Nearly 196 million employable women are outside the workforce. While the Female Labour Force Participation Rate has improved to 41.7%, only 18% of these women are in formal employment. The question is not just how India creates opportunities for women, but how it ensures that these opportunities are visible, measurable, and acted on across every department of governance.

A district-level tool

The launch of the Women's Economic Empowerment (WEE) Index by the Government of Uttar Pradesh – the first in India – offers a glimpse of what is possible. This district-level tool tracks women's participation across five economic levers: employment; education and skilling; entrepreneurship; livelihood and mobility, and safety and inclusive infrastructure. Its significance lies beyond the index. It signals a shift toward embedding a gender lens in every dataset, every department, and every decision.

India produces multiple indices on health, economic well-being and infrastructure. Very few disaggregate this data by gender. Without this lens, gaps remain hidden. Without visibility, reforms stall. And without reforms, exclusion becomes entrenched.

The Government of Uttar Pradesh's Women's Economic Empowerment Index is a model that can be replicated across the country

When inequities become visible, action follows. In Uttar Pradesh's transport sector for instance, data analysis of bus drivers and conductors in the State and the low percentage of women in this segment prompted the department to redesign recruitment strategies and address foundational infrastructure gaps such as women's restrooms in bus terminals. These changes, while modest, are catalytic, and are unlikely to have occurred without gender-specific insights.

The WEE Index shows how such insights can be systematised. By mapping where women drop off – from school to skilling, skilling to work, or entrepreneurship to credit – it moves the conversation beyond participation rates to structural barriers. Consider this striking pattern: while women dominate (more than 50%) enrolment in Uttar Pradesh's skilling programmes, they represent a fraction of registered entrepreneurs, with their access to credit being even more limited. This highlights not only participation gaps but also the systemic barriers to finance and enterprise support – data that can directly inform policy reform.

The need for data from every system

If India is serious about closing its gender gap at scale, gender-disaggregated data must become universal and normative. This requires integrating gender breakdowns into every departmental management information system – from micro, small and medium enterprises to transport to housing – and building the capacity of local governments to collect and use this data effectively to create effective gender action plans. It also calls for moving beyond surface-level counts to track retention, leadership, re-entry, and quality of employment, particularly at stages after Class 12 in school and post-graduation, where female dropout rates surge.

Equally important is the need for a rethink on gender budgeting. Too often, gender budgeting is confined to finance departments or specific women's welfare schemes. True gender budgeting applies a gender lens to every rupee spent – across education, energy, infrastructure, and more. It is simple – you cannot budget for what you do not measure.

Help for States moving ahead

What Uttar Pradesh has piloted is a foundation that can be replicated and scaled. States such as Andhra Pradesh, Maharashtra, Odisha and Telangana have already set trillion-dollar economic goals. To achieve them, they must leverage their gender dividend. A robust framework such as the WEE Index can help States translate intent into implementation – turning data into district-wise gender action plans that guide budget allocations, infrastructure priorities and programmatic reforms.

India's gender gap is not new, but India's response to it must evolve. The solution would involve a fundamental change in how India sees, measures and responds to gender across every level of governance.

The WEE Index is not the finish line but the starting block. It makes visible what has long been invisible and offers a road map to move women from the margins to the mainstream of India's growth story.

दैनिक समाचार विश्लेषण

प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला गया

1. **कम महिला श्रम बल भागीदारी (एफएलएफपी)**
   - वर्तमान दर: 41.7%, लेकिन औपचारिक रोजगार में केवल 18%।
   - 12वीं कक्षा और उच्च शिक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले प्रमुख बच्चे होते हैं।
2. **डेटा में अदृश्य लिंग अंतराल**
   - अधिकांश राष्ट्रीय सूचकांकों (स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, अर्थव्यवस्था) में लिंग-अलग-अलग डेटा का अभाव है।
   - लैंगिक विभाजन के बिना → अंतराल छिपे रहते हैं → सुधार रुक जाते हैं।
3. **महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रणालीगत बाधाएं**
   - कौशल नामांकन (>50%) में महिलाओं का वर्चस्व है, लेकिन पंजीकृत उद्यमियों का एक छोटा सा हिस्सा है।
   - ऋण और उद्यम समर्थन तक सीमित पहुंच गतिशीलता को और प्रतिबंधित करती है।
4. **पायलट: उत्तर प्रदेश में WEE सूचकांक**
   - 5 लीवरों में महिलाओं की भागीदारी को ट्रैक करता है: रोजगार, शिक्षा/कौशल, उद्यमिता, आजीविका और गतिशीलता, और सुरक्षा/बुनियादी ढांचा।
   - उदाहरण: परिवहन क्षेत्र में सुधार (भर्ती रणनीतियाँ, महिलाओं के लिए शौचालय) लिंग डेटा अंतर्दृष्टि से उभरे।

व्यापक संदर्भ

- **स्थैतिक:**
  - संवैधानिक उपबंध: अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 15 (गैर-भेदभाव), अनुच्छेद 39 (ए) (आजीविका का समान अधिकार)।
  - जेंडर बजटिंग (2005) शुरू की गई लेकिन संकीर्ण रूप से लागू है।
  - वैश्विक सूचकांक: ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 (129/146) में भारत निचले स्थान पर है।
- **वर्तमान**:
  - महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों में 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है → लैंगिक समावेशन महत्वपूर्ण है।
  - नीति आयोग का महिला उद्यमिता मंच (WEP)औरगतिशक्तियोजनालिंग-अलग-अलगडेटाको एकीकृत कर सकती है।
  - अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएं: ओईसीडी देश राष्ट्रीय बजट में लिंग विश्लेषण को शामिल करते हैं।

नीतिगत निहितार्थ

1. **मुख्यधारा का लिंग डेटा**
   - प्रत्येक विभागीय एमआईएस (परिवहन, एमएसएमई, आवास, स्वास्थ्य) में लिंग-अलग-अलग संकेतकों को एकीकृत करें।
   - न केवल गिनती पर ध्यान दें, बल्कि प्रतिधारण, नेतृत्व, पुन: प्रवेश और नौकरियों की गुणवत्ता पर भी ध्यान दें।
2. **लिंग बजट पर पुनर्विचार करें**
   - "महिलाओं की योजनाओं" से आगे बढ़ें → खर्च किए गए प्रत्येक रुपये पर लिंग लेंस लागू करें।
   - उदाहरण: महिलाओं की सुरक्षा, गतिशीलता, डिजिटल पहुंच → बुनियादी ढांचा।
3. **जेंडर एक्शन प्लान का स्थानीयकरण**
   - बजट, बुनियादी ढांचे और सुधारों का मार्गदर्शन करने →जिलेवार कार्य योजनाओं के लिए WEE इंडेक्स अंतर्दृष्टि का उपयोग करें।
   - लिंग-संवेदनशील डेटा संग्रह में स्थानीय सरकार की क्षमता का निर्माण करें।
4. **आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करना**

- मैकिन्से का अनुमान है कि महिलाओं की समान भागीदारी 2025 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 770 बिलियन डॉलर जोड़ सकती है।
- कार्यबल के बाहर 196 मिलियन रोजगार योग्य महिलाओं के साथ, भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा अप्रयुक्त श्रम भंडार है।

निष्कर्ष

भारत की विकास महत्वाकांक्षाओं को अपने लिंग अंतर को बंद किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। WEE इंडेक्स दिखाता है कि डेटा दृश्यता कैसे कार्रवाई करती है - अदृश्य असमानताओं को लक्षित सुधारों में बदल देती है। ऐसे उपकरणों को देश भर में स्केल करना और हर नीतिगत निर्णय में लिंग-अलग-अलग डेटा को एम्बेड करना महत्वपूर्ण होगा। सच्चे लिंग बजट का अर्थ है भारत की विकास रणनीति के केंद्र में महिलाओं के साथ मापना, योजना बनाना और निवेश करना।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: निम्नलिखित पर विचार करें:

1. ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स
2. नीति आयोग का महिला उद्यमिता मंच
3. WEE इंडेक्स
4. भारत में जेंडर बजटिंग शुरू की गई

उपरोक्त में से कौन सी भारत-विशिष्ट पहल हैं?

a) केवल 1, 2 और 3

b) केवल 2, 3 और 4

c) केवल 1 और 4

d) केवल 2 और 4

उत्तर: (b)

UPSC Essay Paper Practice Question

1. "आप जो नहीं मापते हैं उसके लिए आप बजट नहीं बना सकते। **(1200 शब्द)**

2. "आधी आबादी, आधी विकास की कहानी। **(1200 शब्द)**

UPSC Essay Paper Practice Question

दैनिक समाचार विश्लेषण

प्रश्न: डेटा सिस्टम में अदृश्यता के कारण महिलाएं भारत की विकास गाथा के हाशिये पर बनी हुई हैं। WEE सूचकांक जैसी हाल की पहलों के संदर्भ में चर्चा करें। **(150 शब्द)**

Page 09 :GS 2 : Social Justice / Prelims

निबंध उद्धरण: "यह निर्णय कानून, पीड़ित विज्ञान और सामाजिक न्याय को जोड़ता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य भारत के गरिमा के संवैधानिक वादे के केंद्र में आता है।

जुलाई 2025 में, सुप्रीमकोर्टनेसुकदेबसाहाबनामआंध्रप्रदेशराज्यमेंमानसिकस्वास्थ्य को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग घोषित किया, जो एक संवैधानिक मील का पत्थर है। 17 वर्षीय नीट उम्मीदवार की दुखद आत्महत्या से प्रेरित, यह मामला एक व्यक्तिगत शिकायत से परे छात्र आत्महत्या, संस्थागत उपेक्षा और राज्य की जिम्मेदारी की प्रणालीगत मान्यता में विस्तारित हो गया। यह फैसला कानूनी, आपराधिक और पीड़ित दृष्टिकोण को संरेखित करता है।

फैसले के मुख्य पहलू

1. **संवैधानिक मान्यता**
   - मानसिक स्वास्थ्य न केवल मानसिक स्वास्थ्य देखभाल

Court's nod to mental health as right

Shabin O.S.
is Assistant Professor, Rashtriya Raksha University, Puducherry campus

Nabeela Siddiqui
is Assistant Professor, Vinayaka Mission's Law School, Vinayaka Missions Research Foundation – Deemed to be University, Chennai

In July 2025, the Supreme Court of India pronounced a verdict which has been called a constitutional landmark. The case, *Sukdeb Saha vs The State Of Andhra Pradesh*, was anchored in the anguish of a father who had lost his 17-year-old daughter, a NEET candidate, in a Visakhapatnam hostel. Dissatisfied with what he believed was the failure of the local police to make a full investigation of the cause, he demanded a Central Bureau of Investigation (CBI) inquiry. His petitions were rejected by the Andhra Pradesh High Court, which then saw him approach the Supreme Court. The result was not only an order shifting the investigation to the CBI but also a much-needed acknowledgment of mental health being an integral part of the right to life, under Article 21 of the Constitution.

The top court's argument transcended the specific case and revolved around a crucial social issue: India's runaway epidemic of student suicides. From a criminological perspective, the case highlights what can be termed structural victimisation. Student suicides are rarely framed in these terms. Yet, systemic neglect of mental health combined with the exploitative culture of coaching centres and the indifference of schools and universities, produce an environment where young people become vulnerable to harm. By failing to provide safeguards, the state and institutions become complicit. When institutions create or ignore conditions that drive individuals to the brink, the line between personal tragedy and institutional culpability becomes blurred.

The gaze of victimology, which has long examined the dynamics between victims and perpetrators, can be extended to state institutions as de facto perpetrators. Students are not just "victims" of internal psychological battles. They are the victims of an education system that treats them shabbily. It is also about social values that link self-esteem to hierarchy and of a governance collapse that subordinates mental health as a secondary concern. By recognising mental health as an inherent right, the Court was recognising the structural aspect of victimisation. It recast the problem not as a personal bereavement but as a public injustice.

Legally, the verdict fills a vital gap. The Mental Healthcare Act 2017 already enshrines the right to receive mental health care. But it has not been implemented consistently, and enforcement mechanisms are still poor. By entrenching mental health in the Constitution, the Court has established an elevated normative benchmark. Citizens can insist on safeguarding their psychic health as a fundamental right, not just a statutory right. To ensure that this did not become mere rhetoric, the Court ordered a package of binding interim orders – now referred to as the "Saha Guidelines". Here, schools, colleges, hostels and coaching institutes are required to proactively develop support systems to address the issue of mental health. They instruct States and Union Territories to bring the rules into force in two months and obligate the setting up of district-level monitoring committees. Until Parliament passes a full code, these guidelines will have legislative force.

The ruling also poses significant criminological questions regarding state responsibility. If suicides among students are partially an outcome of institutional neglect, can this form of neglect be regarded as structural violence? Johan Galtung's theory of structural violence posits that societal structures causing systematic harm to individuals by depriving them of basic needs are equally blameworthy as direct violence. By not creating a safe environment, the state and educational institutions indirectly perpetuate harmful circumstances. This perspective changes student suicides from being viewed as "individual failures" to a result of systemic injustice. As a victimology case, it is a point where hidden victims become visible. Students, frequently silenced by stigma or system competitiveness, are seldom heard as rights holders when it comes to mental health. Placing psychological integrity in Article 21 means that the Court has opened up room for these victims to be heard and safeguarded. It leaves the door ajar for restorative measures – counselling, reform in institutions, mechanisms of accountability that go beyond retribution to prevention.

The way the judgment has been received by mental health activists and professionals highlights its revolutionary potential. But along with optimism there must be caution. Powerful judicial pronouncements cannot, by themselves, uproot established cultural and institutional norms. The challenge is whether schools, universities, and State governments will meaningfully apply the guidelines, invest in resources, and train personnel to deliver real mental health care.

Ultimately, *Sukdeb Saha* represents a convergence of law, criminology and victimology. It recognises that harm can be produced not just by individuals but also by institutions and systems. It acknowledges that students, often treated as passive subjects of education, are rights holders whose mental well-being deserves constitutional protection. And, it challenges society to confront an uncomfortable truth – that neglect, indifference and structural pressures can be as deadly as acts of direct violence. In affirming that the right to life must include a healthy mind, the Court has given voice to a generation of students who have too often been silenced by despair. Whether this voice translates into meaningful change will determine whether the judgment remains a beacon of hope or a missed opportunity.

The Supreme Court's judgment in 'Sukdeb Saha vs The State Of Andhra Pradesh', acknowledges mental health to be an integral part of the right to life

अधिनियम, 2017 के तहत एक वैधानिक अधिकार है , बल्कि अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार→।
- ऊंचा मानक बेंचमार्क: नागरिक प्रवर्तन की मांग कर सकते हैं।

2. **"साहा दिशानिर्देश" (बाध्यकारी अंतरिम आदेश)**
   - स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्टल और कोचिंग सेंटरों → सपोर्ट सिस्टम स्थापित करने होंगे।
   - राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 2 महीने के भीतर नियम बनाने →।
   - अनुपालन के लिए जिला स्तरीय निगरानी समितियां।
   - संसद द्वारा एक व्यापक संहिता लागू होने तक विधायी बल के लिए दिशा-निर्देश।
3. **पीड़ित विज्ञान और संरचनात्मक हिंसा**
   - छात्र आत्महत्याओं को व्यक्तिगत विफलता के बजाय संरचनात्मक उत्पीड़न के रूप में तैयार किया गया है।
   - उपेक्षा के कारण राज्य और संस्थानों को वास्तविक अपराधियों के रूप में देखा जाता है।
   - जोहान गाल्टुंग के "संरचनात्मक हिंसा" सिद्धांत का अनुप्रयोग → प्रणालीगत नुकसान प्रत्यक्ष हिंसा के बराबर है।
4. **जवाबदेही और रोकथाम**
   - परामर्श → प्रतिशोध से पुनर्स्थापनात्मक न्याय की ओर विमर्श को आगे बढ़ाता है , संस्थागत सुधार, निवारक उपाय।
   - छात्रों को अधिकार धारकों के रूप में मान्यता देता है, निष्क्रिय विषयों के रूप में नहीं।

व्यापक संदर्भ

- **वैधानिक ढांचा:**
  - मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 – सस्ती, सुलभ मानसिक स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार; आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से बाहर करना (धारा 115)।
  - राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 - कल्याण और परामर्श पर ध्यान केंद्रित करें, लेकिन सीमित कार्यान्वयन।
- **वर्तमान संकट**:
  - भारत विश्व स्तर पर सबसे अधिक छात्र आत्महत्या दर वाले देशों मेंसेएकहै। एनसीआरबीकेआंकड़े: सालाना >13,000 छात्र आत्महत्या करते हैं।
  - कोटा, हैदराबाद और अन्य कोचिंग हब बार-बार होने वाली त्रासदियों के गवाह बनते हैं।
  - डब्ल्यूएचओ का अनुमान: 7 में से 1 भारतीय मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से पीड़ित है, लेकिन प्रति 1.3 लाख लोगों पर केवल 1 मनोचिकित्सक (उपचार में भारी अंतर) है।
- **संवैधानिक कोण**:
  - अनुच्छेद 21 का विस्तार: आजीविका के अधिकार (ओल्गा टेलिस, 1985) से गोपनीयता (पुट्टास्वामी, 2017) तक, अब मानसिक स्वास्थ्य तक।
  - निर्देशक सिद्धांतों (अनुच्छेद 41 - सार्वजनिक स्वास्थ्य) और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं (मानसिक स्वास्थ्य पर यूएनसीआरपीडी, एसडीजी -3) को सुदृढ़ करता है।

निष्कर्ष

सुकदेबसाहाकाफैसलाभारतकेअधिकारन्यायशास्त्र में एक परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है – यह स्वीकार करते हुए कि मानसिक कल्याण जीवन के अधिकार से अविभाज्य है। यह छात्र आत्महत्याओं को प्रणालीगत उपेक्षा से पैदा हुए सार्वजनिक अन्याय के रूप में फिर से परिभाषित करता है, न कि केवल निजी त्रासदियों से। फिर भी, इसकी सफलता साहा दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन, संसाधन आवंटन और शिक्षा प्रणालियों में सांस्कृतिक परिवर्तन पर निर्भर करेगी। यदि प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो यह निर्णय कलंक और चुप्पी से जवाबदेही और देखभाल की ओर एक आदर्श बदलाव की शुरुआत को चिह्नित कर सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सकता है कि भारत के युवा न केवल अकादमिक रूप से, बल्कि मानसिक रूप से भी फलते-फूलते रहें।

दैनिक समाचार विश्लेषण

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: हाल ही में, "साहा दिशानिर्देश" खबरों में रहे हैं। वेइससेसंबंधितहैं:

a) डिजिटल डेटा सुरक्षा

b) मानसिकस्वास्थ्यसुरक्षा

c) महिला आरक्षण

d) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन

उत्तर : b)

UPSC Mains Practice Question : Paper 4

प्रश्न: उपेक्षा और संस्थागत उदासीनता प्रत्यक्ष हिंसा के रूप में घातक हो सकती है। मानसिक स्वास्थ्य पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में, संरचनात्मक हिंसा और छात्र आत्महत्याओं के संदर्भ में इस कथन की गंभीर जांच करें। **(150 शब्द)**

दैनिक समाचार विश्लेषण

Page : 10: GS 2 : Indian Polity/ Prelims

निबंध उद्धरण :कानून का शासन उत्पीड़ितों के पक्ष में मजबूती से खड़ा होना चाहिए, उत्पीड़क के पक्ष में नहीं।

1 सितंबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने किरण बनाम राजकुमार जीवराज जैन के मामले में जातिगत अत्याचार के एक मामले में एक आरोपी को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत रद्द कर दी। सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत पर रोक को बरकरार रखा, यह कहते हुए कि यह अधिनियम दलितों और आदिवासियों के लिए प्रणालीगत जाति-आधारित हिंसा, धमकी और भेदभाव के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा के रूप में कार्य करता है।

मामले के तथ्य

- **एफआईआर (26 नवंबर, 2024):** शिकायतकर्ता (एससी समुदाय) ने विधानसभा चुनावों में मतदान की पसंद से जुड़े हमले, जातिगत दुर्व्यवहार, परिवार की महिला सदस्यों के साथ छेड़छाड़, लूटपाट और धमकियां देने का आरोप लगाया।
- **सत्र न्यायालय:** जातिवादी इरादे और पुष्टि का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत सेइनकारकियागया।
- **बॉम्बे हाई कोर्ट (औरंगाबाद बेंच):** मामले

SC on anticipatory bail in caste crime

Supreme Court cancels anticipatory bail granted to a caste crime accused, upholding Section 18 of the SC/ST Act; the ruling reinforces protection for Dalit victims, bars pre-trial relief, and warns courts against conducting a 'mini-trial' at the bail stage

LETTER & SPIRIT

Vikram Karuna

The story so far:

On September 1, the Supreme Court quashed a Bombay High Court order that had granted anticipatory bail to an accused of caste crimes. In the case of *Kiran vs Rajkumar Jivaraj Jain*, a Bench led by Chief Justice of India B. R. Gavai held that Section 18 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, creates a specific bar against anticipatory bail for crimes made out *prima facie*. This case involves caste-based assault, abuse, and intimidation linked to an electoral dispute.

Facts of the case

In this case, on November 26, 2024, a First Information Report (FIR) was filed by Kiran, a member of the Scheduled caste community, alleging that Rajkumar Jain and others had attacked him and his family after he refused to cast a vote as directed in the Assembly elections. According to the complaint, the accused attacked him with iron rods, abused him with his caste name, molested his mother and aunt, looted the *mangalsutra*, and threatened to burn their home with petrol bottles. The incident was witnessed by independent witnesses. The Additional Sessions judge at Paranda rejected anticipatory bail, noting clear casteist intent and corroboration. However, the Bombay High Court (Aurangabad Bench) reversed this decision, terming the case politically motivated, exaggerated, and inconsistent, and granted bail. This prompted an appeal before the Supreme Court.

Why is anticipatory bail barred under the SC/ST Act?

The Supreme Court underlined that Section 18 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, categorically excludes the application of Section 438 of the Criminal Procedure Code (CrPC) (Section 482 of BNSS), which allows anticipatory bail. The Parliament has inserted this bar to protect victims from intimidation and to ensure effective prosecution.

Drawing upon precedents such as *State of M.P. vs Ram Krishna Balothia* (1995), *Vilas Pandurang Pawar vs State of Maharashtra* (2012), and *Prathvi Raj Chauhan vs Union of India* (2020), the court reiterated that offences under the Act form a distinct class tied to systemic untouchability and caste discrimination. The bar is constitutionally valid and does not violate Article 14 or 21 of the Constitution. Courts, the Bench clarified, cannot conduct a "mini-trial" at the bail stage and are only required to examine whether a prima facie case exists.

In this case, the use of caste slurs, the public nature of the assault, and the electoral motive made the offence squarely fall within the ambit of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, thereby ruling out anticipatory bail.

GETTY IMAGES

Key observations

The Bench clarified that insults and assaults that occur outside the complainant's house, in a manner visible to others, count as acts "within public view," a statutory requirement under Section 3(1)(r). It further noted that the attack was triggered by the complainant's voting choice, which attracted Section 3(1)(o) of the Act that criminalises coercion or retaliation in voting against SC/ST members. Independent witness accounts, recovery of weapons, and medical evidence strengthened the prosecution's case, making the High Court's dismissal of the FIR untenable. The court also cautioned High Courts against overstepping into evidence appreciation at the pre-arrest bail stage.

Ultimately, the Supreme Court cancelled the anticipatory bail, calling the High Court's order a "manifest error and jurisdictional illegality."

The way forward

The ruling reinforces that the SC/ST Act is not a procedural formality but a substantive shield to safeguard the dignity and security of vulnerable communities. The bar on anticipatory bail, although strict, is constitutionally sound because it addresses the very real threat of intimidation and retaliation against Dalit and tribal complainants.

Going forward, courts must respect the legislative intent of Section 18 and avoid diluting its force by treating allegations as exaggerated without trial, and apply the "*prima facie* test" strictly on the face of the FIR, without slipping into evidentiary analysis. The judgment also recognises that electoral retaliation against SC/ST voters carries broader implications for democratic participation and social justice.

The judgment strengthens accountability under the SC/ST Act and underscores that the rule of law must stand firmly on the side of protecting the most marginalised.

Vikram Karuna is an Assistant Professor at the School of Law, Justice & Governance, Gautam Buddha University, Greater Noida

THE GIST

- The court cancels anticipatory bail in *Kiran vs Rajkumar Jivaraj Jain*, reaffirming that Section 18 of the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989 bars anticipatory bail for offences like caste-based assault, abuse, intimidation, and electoral retaliation.
- The judgment emphasises that courts must respect the bar on anticipatory bail, avoid mini-trials at the pre-arrest stage, and apply the *prima facie* test, reinforcing protection of vulnerable SC/ST communities and accountability for caste crimes.

को "राजनीति से प्रेरित" बताते हुए पलटे फैसले को जमानत दे दी गई।
- **सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के** आदेश को पलटते हुए एससी/एसटी एक्ट के तहत अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी है।

एससी/एसटी एक्ट के तहत अग्रिम जमानत पर रोक क्यों है?

- अधिनियम की धारा 18: स्पष्ट रूप से धारा 438 सीआरपीसी (अग्रिम जमानत) को बाहर करती है।
- संसद का इरादा: पीड़ितों को डराने-धमकाने से रोकें और प्रभावी अभियोजनकीरक्षाकरें।

- **SC** द्वारा बरकरार रखी गई मिसालें:
  - मध्य प्रदेश राज्य बनाम राम कृष्ण बलोठिया (1995) - धारा 18 मान्य, अनुच्छेद 14/21 का उल्लंघन नहीं है।
  - विलास पांडुरंग पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2012) – अग्रिम जमानत की अनुमति नहीं।
  - पृथ्वीराजचौहानबनामभारतसंघ (2020) – अग्रिम जमानत पर रोक की पुष्टि की।

मुख्य सिद्धांत: अदालत को केवल प्रथम दृष्टया मामले की जांच करनी चाहिए; जमानत के स्तर पर कोई "मिनी-ट्रायल" नहीं होना चाहिए।

SC की मुख्य टिप्पणियाँ

1. **"सार्वजनिक दृष्टिकोण" आवश्यकता** - पीड़ित के घर के बाहर जाति-आधारित अपमान/हमले, जो दूसरों को दिखाई देते हैं, धारा 3 (1) (आर) के तहत योग्य हैं।
2. **चुनावी प्रतिशोध** – अपराध धारा 3 (1) (ओ) (मतदान में जबरदस्ती/प्रतिशोध) के तहत आता है।
3. **साक्ष्य सीमा** - स्वतंत्र गवाह, हथियारों की बरामदगी, और चिकित्सा साक्ष्य → पर्याप्त प्रथम दृष्टया मामला।
4. **उच्च न्यायालय की त्रुटि** - आरोपों को अतिरंजित मानना "क्षेत्राधिकार अवैधता" के बराबर है।
5. **लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षण** – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं के खिलाफ चुनावी हिंसा लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को कमजोर करती है।

व्यापक संदर्भ

- **एससी/एसटी अधिनियम, 1989**: दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार को रोकने केलिएऐतिहासिककानून।
- **संशोधन (2018):** पृथ्वी राजचौहानविवादकेबादमजबूतसुरक्षाबहालकीगई ; अग्रिमजमानत बार को स्पष्ट किया गया।
- **संवैधानिक सुरक्षा उपाय**:
  - अनुच्छेद 17 → अस्पृश्यता का उन्मूलन।
  - अनुच्छेद 15(2), 15(4), 16(4) → सुरक्षात्मक भेदभाव।
- **वर्तमान मुद्दे**: एनसीआरबी के आंकड़े दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अत्याचारों में लगातार वृद्धि दिखाते हैं; दुरुपयोग के तर्क अक्सर उठाए जाते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट अधिनियम की आवश्यकता कीपुष्टिकरताहै।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस बात की पुष्टि करता है कि एससी/एसटी अधिनियम एक ठोस ढाल है, न कि प्रक्रियात्मक औपचारिकता। धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत पर सख्त रोक संवैधानिक रूप से वैध है और दलित और आदिवासी पीड़ितों को धमकाने से रोकने के लिए आवश्यक है। अदालतों को विधायी इरादे का सम्मान करना चाहिए, जमानत के चरण में मिनी-ट्रायल करने से बचना चाहिए, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सबसे हाशिए पर रहने वाले लोगों की गरिमा, समानता और लोकतांत्रिक अधिकार सुरक्षित रहें।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न : निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 18 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है?

a) मध्य प्रदेश राज्य बनाम राम कृष्ण बलोठिया (1995)

b) मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)

c) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)

d) नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018)

उत्तर: a

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: अदालतों को विशेष क़ानून के तहत अग्रिम जमानत का फैसला करते समय 'मिनी-ट्रायल' करने से बचना चाहिए। किरण बनाम राजकुमार जीवराज जैन (2024) में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के संदर्भ में चर्चा करें। **(150 शब्द)**

Page 12 :GS 3 : Indian Economy / Prelims

भारत 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आने वाले दशकों में निरंतर 8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि हासिल करने की आकांक्षा रखता है। हाल ही में नीति आयोग की एक रिपोर्ट (2025) ने वर्तमान विकास दर और इस लक्ष्य के बीच के अंतर को पाटने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की परिवर्तनकारी भूमिका पर प्रकाश डाला। फार्मास्यूटिकल्स, विनिर्माण, ऑटोमोबाइल और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में पहले से ही महत्वपूर्ण क्षमता दिखाई दे रही है, एआई को उत्पादकता, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के प्रमुख चालक के रूप में पेश किया जाता है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

1. **विकास चालक के रूप में एआई**
   - एआई क्षमता 8% वार्षिक जीडीपी वृद्धि हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।
   - कई उद्योगों में उत्पादकता में सुधार की उम्मीद है।
2. **क्षेत्रीय प्रभाव**
   - **फार्मास्यूटिकल्स**:
     - एआई दवा की खोज लागत को 10 गुना कम कर देता है।
     - समय-समय पर बाजार में ~ 10 साल से ~ 5 साल तक कटौती करता है।
     - भारत के लिए वैश्विक दवा नवाचार केंद्र बनने का मार्ग खोलता है।
   - विनिर्माण और ऑटोमोबाइल: पूर्वानुमानित रखरखाव, गुणवत्ता नियंत्रण और स्मार्ट आपूर्ति श्रृंखला।
   - वित्तीय सेवाएँ: जोखिम प्रबंधन, धोखाधड़ी का पता लगाना और व्यक्तिगत सेवाएँ।

'AI-led efficiencies can contribute to 8% GDP growth target'

Aroon Deep
NEW DELHI

Skilling workers whose roles are threatened by AI is key, NITI Aayog said in the report

Artificial Intelligence-led efficiencies in industries could be key in contributing to an annual Gross Domestic Product (GDP) growth rate of 8% in the coming years, NITI Aayog said in a report on Monday.

"Accelerating AI adoption across industries to improve productivity and efficiency could bridge 30-35% of the gap between the current rate of growth and the 8% target," the public policy think tank said in the report.

Individual industries must leverage AI to introduce efficiencies; candidates that are primed for this include pharmaceuticals, manufacturing, automobiles and financial services, it said.

"AI has reduced the cost of producing the next molecule [for the pharmaceutical industry] by approximately 10 times and crashed the time that it takes – roughly 10 years – by roughly 50%," Koshir Daka, a senior partner at McKinsey said at the report unveiling, adding that this could give India an opening to invent a clutch of drugs at a global stage in the near future.

The unveiling is among a series of events building up to February 2026's AI Impact Summit, to be hosted by India.

"The impact that AI can have, not just on India's economy but the global economy, is so profound and so significant that we need to take the leadership position in this area," IT Secretary S. Krishnan said.

Skilling workers whose roles are threatened by AI is key, the report said, recommending "mapping job shifts annually, embedding lifelong learning into career pathways, scaling MSME digital upskilling, and protecting gig and platform workers."

3. **एआई और नौकरियां**
    - कुछ भूमिकाओं में विस्थापन का जोखिम।
    - रिपोर्ट अनुशंसा करती है:
        - नौकरी की शिफ्ट की वार्षिक मैपिंग।
        - करियर के रास्ते में आजीवन सीखने को शामिल करना।
        - एमएसएमई डिजिटल अपस्किलिंग को बढ़ाना।
        - गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए सुरक्षा।
4. **भारत की वैश्विक स्थिति**
    - फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट निर्धारित है, जो वैश्विक एआई शासन और नवाचार में नेतृत्व करने के भारत के इरादे को प्रदर्शित करता है।
    - आईटी सचिव एस. कृष्णन: एआई का प्रभाव विश्व स्तर पर "गहरा और महत्वपूर्ण" होगा, और भारत को खुद को सबसे आगे रखना चाहिए।

स्थिर और वर्तमान संदर्भ

- **स्थैतिक**:
    - एआई = मशीनों द्वारा मानव बुद्धि प्रक्रियाओं का अनुकरण (सीखना, तर्क, आत्म-सुधार)।
    - जीएस-3 (विज्ञान और तकनीक, अर्थव्यवस्था),जीएस-2 (गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया) के लिए प्रासंगिक।
    - नीति आयोग की पहले की पहल: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्रीय रणनीति (2018) – "सभी के लिए एआई"।
- **वर्तमान**:
    - भारत का AI इकोसिस्टम: स्टार्ट-अप, डिजिटल इंडिया स्टैक (आधार, UPI, ONDC), और AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क के लिए सरकार का प्रयास।
    - वैश्विक दौड़: अमेरिका और चीन का प्रभुत्व; यूरोपीय संघ एआई विनियमन पर ध्यान केंद्रित करता है। भारत एक संतुलित मॉडल चाहता है।
    - रोजगार की चुनौती: ILO की रिपोर्ट है कि स्वचालन भारत के औपचारिक क्षेत्र में ~69% नौकरियों को प्रभावित कर सकता है।

एआई अपनाने में चुनौतियाँ

- डेटा की गुणवत्ता और पहुंच।
- एआई बुनियादी ढांचे की उच्च लागत (कंप्यूट पावर, चिप्स, क्लाउड)।
- कौशल अंतर - एआई शोधकर्ताओं और चिकित्सकों की कमी।
- नैतिक चिंताएं - गोपनीयता, पूर्वाग्रह, जवाबदेही।
- असमान पहुंच - एमएसएमई और ग्रामीण क्षेत्र अपनाने में पिछड़ गए हैं।

भारत के लिए निहितार्थ

1. आर्थिक: उत्पादकता, लागत दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा।
2. सामाजिक: नौकरी विस्थापन का जोखिम; कौशल और सुरक्षा जाल की आवश्यकता।
3. रणनीतिक: एआई शासन में नेतृत्व भारत के वैश्विक प्रभाव को मजबूत करता है।
4. समावेशी विकास: एमएसएमई डिजिटल अपनाना, गिग वर्कर सुरक्षा और क्षेत्रीय समावेशन आवश्यक।

निष्कर्ष

एआई को अपनाना भारत के लिए न केवल एक तकनीकी अनिवार्यता है बल्कि एक आर्थिकरणनीतिहै। सकलघरेलूउत्पाद की वृद्धि में तेजी लाने, नवाचार को बढ़ाने और भारत को वैश्विक एआई हब के रूप में स्थापित करने की क्षमता के साथ, चुनौती नौकरी में बदलाव, नैतिक एआई और समावेशी अपनाने के प्रबंधन में है। यदि अच्छी तरह से उपयोग किया जाता है, तो एआई India@2047 विकास की कहानी का एक प्रमुख स्तंभ हो सकता है, जो व्यवधान को अवसर में बदल सकता है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: भारत में "सभी के लिए जिम्मेदार एआई" पहल मुख्य रूप से निम्नलिखित से जुड़ी है:

a) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)

b) नीति आयोग

c) भारतीय रिजर्व बैंक

d) विज्ञानऔरप्रौद्योगिकीमंत्रालय

उत्तर: b)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आने वाले वर्षों में 8% जीडीपी वृद्धि हासिल करने के भारत के लक्ष्य का एक प्रमुख चालक होने का अनुमान है। सभी क्षेत्रों में एआई अपनाने के अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करें, और समावेशी और जिम्मेदार एआई-संचालित विकास सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत उपाय सुझाएं। **(150 शब्द)**

दैनिक समाचार विश्लेषण

Page : 08 Editorial Analysis

दैनिक समाचार विश्लेषण

Unlocking innovation with India's procurement reforms

Procurement policies, often designed with transparency and cost-efficiency in mind, have long had unintended consequences for research and development. While preventing fraud, these frameworks frequently kill innovation, one process at a time, by prioritising procedural compliance over scientific needs. India's recent reforms to its General Financial Rules (GFR) – particularly exemptions from the Government e-Marketplace (GeM) portal and enhanced financial thresholds for research and development (R&D) procurement – are a welcome change.

Arindam Goswami

is a Research Analyst in the High-Tech Geopolitics Programme at The Takshashila Institution, Bengaluru

Procurement as innovation catalyst

The tug-of-war between procurement policies and innovation is not new. Studies have shown that public procurement, when done properly, can give a push to private-sector R&D by creating stable demand for advanced technologies. Moreover, it has been found that targeted procurement spending is associated with increased patent filings and private R&D investment, forming a virtuous cycle of innovation. However, as the Brazilian case study in EconStor's 2023 report notes, generic procurement rules rarely achieve this unless explicitly designed to spur innovation. India's pre-reform framework fell into this trap: mandating GeM purchases for all sub-₹200 crore equipment, regardless of specialisation, which forced scientists into a time-consuming exemption process for globally benchmarked tools. Vendors on GeM often supplied materials of poor quality, compromising research.

The Government of India's policy changes in June 2025 directly address these issues. By allowing institutional heads to bypass GeM for specialised equipment and raising direct purchase limits from ₹1 lakh to ₹2 lakh, the reforms acknowledge that cookie-cutter procurement is incompatible with R&D's bespoke needs. Delegating approval for global tenders up to ₹200 crore to vice-chancellors and directors eliminates bureaucratic lag – a chronic grievance highlighted by the Prime Minister's Economic Advisory Council. These adjustments align with theories of "catalytic procurement", where flexibility enables public institutions to act as early adopters of advanced technologies, stimulating private-sector innovation.

Yet, the reforms stop short of a full paradigm shift. While empowering institutional leaders, they retain safeguards such as departmental purchase committees for higher-value acquisitions. This could be argued as a necessary balance. However, even the revised ₹2 lakh direct purchase limit could remain inadequate for high-cost fields such as quantum computing or biotechnology. Additionally, the focus on global tenders, while ensuring quality, could marginalise domestic suppliers unless local R&D systems are empowered and left free to collaborate globally, and compete at that level.

The policy's success will depend to a large extent on implementation. Trusting institutional heads with procurement discretion assumes high ethical standards, which is something that will have to be built up, slowly, in a system that has been historically plagued by inefficiency. As the policy rolls out, monitoring mechanisms will be vital to prevent misuse while preserving agility.

Research and development can be transformed by blending these changes with global best practices in market-shaping, cognitive tools and hybrid governance

How has procurement evolved globally? Globally, nations leading in R&D outcomes have already reimagined procurement as something that acts as a catalyst for innovation – not just a cost-control mechanism. India can learn from their experiences. Procurement processes have evolved from ancient record-keeping to Artificial Intelligence (AI)-driven strategies. India would do well to learn from these.

Germany's approach is a good example of balancing procurement checks and R&D ambitions. Through its High-Tech Strategy, the federal government mandates that public procurement be used to promote innovative solutions, supported by KOINNO, which is a dedicated agency advising procurers, curating supplier databases, and hosting cross-sector innovation forums. This institutionalises what economist Mariana Mazzucato terms "mission-oriented procurement", where state-purchasing power deliberately shapes technological markets. Similarly, the 'Small Business Innovation Research (SBIR) program' of the United States reserves 3% of federal R&D funds for startups, using phased procurement contracts to derisk early-stage technologies while maintaining competitive tension among vendors. These models recognise that procuring innovation is not about buying predefined products but in fostering ecosystems where suppliers compete on breakthroughs.

India's GeM reforms partially embrace this philosophy by exempting specialised research equipment from mandatory portal use – a nod to the fact that Indian labs often face delays extending to a few months when dealing with niche instruments. However, the policy lacks Germany's proactive market-shaping elements or the SBIR's staged funding structure. For instance, India's ₹200 crore global tender limit for institutional heads still prioritises cost benchmarks over technical ambition, unlike South Korea's "pre-commercial procurement" system that pays premium prices for prototypes meeting moonshot criteria.

Procurement's evolutionary arc

Procurement's 5,000-year journey, from Egyptian scribes tracking pyramid materials to AI predicting supply chain details, reflects an evolution from control to creativity. The Industrial Revolution looked at procurement as a cost-centric function, but the two World Wars exposed its strategic role in securing scarce resources.

Post-1945, this duality deepened: corporations adopted Just-In-Time inventory systems while governments used procurement to spur sectors such as semiconductors (via National Aeronautics and Space Administration contracts) and renewables (through the European Union's green mandates).

Today's frontier is "cognitive procurement", where tools such as generative AI analyse supplier ecosystems, simulate scarcity scenarios, and automate compliance – freeing researchers to focus on creative sourcing. Consider Pfizer's COVID-19 vaccine effort, where AI-optimised procurement identified multiple critical suppliers within a few hours, compressing a months-long process into weeks.

The discussion over procurement policies often leads to calls for privatisation of national labs, as that would probably open up the procurement process. However, it would be wise to consider that the debate over privatising India's national labs hinges on a false binary. As the U.S. experience shows, privatisation is not about abandoning public oversight but redefining it. When the Department of Energy handed over the management and operation of Sandia National Laboratories in 1993 to a private company, it retained mission control through performance-based contracts while unlocking private capital for laser and materials research. The result? A huge increase in patent filings and partnerships with a number of small and medium enterprises within a decade.

India's Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) could adopt this hybrid model. Laboratories working in strategic fields such as space tech or quantum computing might benefit from corporate-style agility in procurement and hiring, provided the government maintains some control to safeguard national interests. However, success requires robust accountability frameworks and some alignment with innovation road maps.

Procurement as a research variable

India's procurement reforms are necessary but insufficient. Four systemic shifts could anchor deeper change. The first would be outcome-weighted tenders. Following Finland's example, there must be an evaluation of bids not just on cost but also on an index that weighs various qualitative factors such as supplier R&D investment and scalability potential.

The second would be providing sandbox exemptions. Allow institutions such as the Tata Institute of Fundamental Research or the Indian Institutes of Technology to bypass GFR entirely for some percentage of their purchases, provided they meet annual innovation targets audited by third parties.

The third intervention should be AI-augmented sourcing. Deploy the INDIAai ecosystem to create a procurement assistant that scans global catalogues, predicts customs delays, and suggests alternative materials – reducing decision cycles from months to hours.

And finally, go in for co-procurement alliances. Replicate the European Union's Joint Procurement Agreement, enabling multiple Indian labs to aggregate demand for high-cost items such as cryogenic coolers, achieving economies of scale.

Privatisation is not a silver bullet but a tool among many. As this study on U.S. labs warns, merely transferring ownership sans performance-linked funding or competitive pressure risks creating ineffective labs. The goal must be creating a procurement continuum where public and private entities coexist – each accessing shared innovation marketplaces but governed by distinct risk-reward matrices.

India's GeM reforms are a tentative step toward procurement systems that value time-to-lab as much as cost savings. By marrying these changes with global best practices in market-shaping, cognitive tools, and hybrid governance, the nation could transform procurement from a research impediment to its accelerant. The lesson from history is clear: civilisations that procured for monuments left ruins; those that procured for inquiry built futures.

GS. Paper 03 – विज्ञानऔर प्रौद्योगिकी

UPSC Mains Practice Question: भारतमेंखरीद नीतियों ने ऐतिहासिक रूप से रचनात्मकता पर अनुपालन को प्राथमिकता दी है। चर्चा करें कि सामान्य वित्तीय नियमों में हाल के सुधार खरीद को नवाचार के चालक में बदलने में कैसे मदद कर सकते हैं। अतिरिक्त उपाय सुझाएं।(150 शब्द)

दैनिक समाचार विश्लेषण

संदर्भ:

खरीद को अक्सर लागत-नियंत्रण और पारदर्शिता तंत्र के रूप में देखा जाता है, लेकिन अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) के लिए, कठोर नियम अड़चन बन सकते हैं। भारत के हालिया सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) सुधार (जून 2025), विशेष रूप से विशेष उपकरणों के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) से छूट और बढ़ी हुई वित्तीय सीमा, नवाचार के लिए संभावित उत्प्रेरक के रूप में खरीद को मान्यता देने की दिशा में एक बदलाव को चिह्नित करते हैं।

सुधारों की मुख्य विशेषताएं

1. विशेषवैज्ञानिकउपकरणोंके लिए जीईएम से छूट → खराब गुणवत्ता वाले विक्रेताओं और देरी से बचाती है।
2. सीधे खरीद की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख →की गई।
3. संस्थागत प्रमुखों (वीसी/निदेशकों) को 200 करोड़ रुपये तक की वैश्विक निविदाओं को मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है।
4. संतुलित सुरक्षा उपाय: अभी भी उच्च-मूल्य खरीद के लिए विभागीय खरीद समितियों की आवश्यकता है।

नवाचार के लिए खरीद क्यों मायने रखती है

- **वैश्विक साक्ष्य**:
  - ब्राज़ील (2023 इकोनस्टोर रिपोर्ट): जेनेरिक खरीद अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देनेमेंविफलरही।
  - जर्मनी की KOINNO: मिशन-उन्मुख खरीद इसकी हाई-टेक रणनीति के अनुरूप है।
  - यूएस एसबीआईआर कार्यक्रम: स्टार्टअप्स के लिए संघीय अनुसंधान एवं विकास निधि का 3% आरक्षित करताहै→ प्रारंभिकनवाचारकोकमकरताहै।
  - दक्षिण कोरिया की पूर्व-वाणिज्यिक खरीद: "मूनशॉट" लक्ष्यों को पूरा करने वाले प्रोटोटाइप के लिए प्रीमियम काभुगतानकरताहै।
- भारत की समस्या: पहले के कठोर जीईएम नियमों ने खरीद में देरी की, प्रयोगशालाओं को हतोत्साहित किया, और बायोटेक, क्वांटम कंप्यूटिंग और रक्षा प्रौद्योगिकियों जैसे उच्च तकनीक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धामेंबाधाडाली।

2025 के सुधारों के लाभ

- लचीलापन: वैज्ञानिक अब एक आकार-फिट-सभी पोर्टल नियमों से बंधे नहीं हैं।
- तेज़ खरीद: नौकरशाही का अंतराल कम हुआ।
- उत्प्रेरक खरीद: प्रयोगशालाओं को शुरुआती अपनाने वालों के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है, निजी क्षेत्र के नवाचार को प्रोत्साहित करता है।
- वैश्विक एकीकरण: वैश्विक विक्रेताओं तक पहुंच खोलकर प्रतिस्पर्धी गुणवत्ता को प्रोत्साहित करता है।

चुनौतियां और कमियां

1. थ्रेसहोल्ड अभी भी कम: ₹2 लाख की सीधी खरीद फ्रंटियर रिसर्च टूल्स के लिए अपर्याप्त हो सकती है.
2. दुरुपयोग का जोखिम: संस्थागत प्रमुखों के लिए अधिक विवेकाधिकार के लिए मजबूत जवाबदेही ढांचे की आवश्यकता होती है।
3. घरेलू आपूर्तिकर्ताओं की चिंता: वैश्विक निविदाएं भारतीय विक्रेताओं को तब तक दरकिनार कर सकती हैं जब तक कि घरेलू अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्तनहींबनायाजाता।

4. अभी तक कोई बाजार-आकार देने वाला तत्व नहीं है: जर्मनी या एसबीआईआर के विपरीत, सुधारों में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय तंत्र का अभाव है।

आगे की राह - सुझाए गए प्रणालीगत बदलाव

1. परिणाम-भारित निविदाएं (फिनलैंड मॉडल): नवाचार क्षमता पर बोलियों का मूल्यांकन करें, न कि केवल लागत।
2. सैंडबॉक्स छूट: आईआईटी, आईआईएससी, सीएसआईआर प्रयोगशालाओं को नवाचार लक्ष्यों के अधीन जीएफआर नियमों को सीमित बायपास करने की अनुमति दें।
3. एआई-संचालित खरीद: देरी की भविष्यवाणी करने, वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं को स्कैन करने और विकल्पसुझानेकेलिएINDIAaiकाउपयोगकरें।
4. सह-खरीद गठबंधन: महंगी वस्तुओं के लिए प्रयोगशालाओं में पूल की मांग (यूरोपीय संघ संयुक्त खरीद समझौता मॉडल)।
5. हाइब्रिड सार्वजनिक-निजी शासन: यूएस सैंडिया लैब्स मॉडल → तरह निजी शैली की चपलता + सार्वजनिक मिशन नियंत्रण।

निष्कर्ष

भारत के खरीद सुधार कठोर लागत-नियंत्रण से नवाचार-सक्षम शासन की ओर बढ़ने की दिशा में एक आवश्यक पहला कदम है। हालांकि, खरीद को वास्तव में अनुसंधान एवं विकास के चालक में बदलने के लिए, भारत को मिशन-उन्मुख खरीद, एआई-संचालित सोर्सिंग और हाइब्रिड गवर्नेंस मॉडल में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना चाहिए। सही तरीके से किया गया, खरीद अब नौकरशाही की बाधा नहीं होगी, बल्कि भारत की नवाचार अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए एकरणनीतिकलीवरहोगी।

NITIN SIR CLASSES

NITIN SIR CLASSES

STARING 4TH OCT 2025

प्रारम्भ बैच (PT BATCH 2026)

- DURATION : 7 MONTH
- DAILY CLASSES : 2 (90 MIN EACH)
- BOOKS - PT ORIENTED PYQ'S
- MAGZINE : HARD + SOFT COPY
- TEST SERIES WITH DISCUSSION
- DAILY THE HINDU ANALYSIS
- MENTORSHIP (PERSONALISED)
- BILINGUAL CLASSES
- DOUBT SESSIONS

ONE TIME PAYMENT
RS 17,500/-

PAY IN 2 EASY INSTALMENTS
RS 20,000/-

Register Now https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR) 99991 54587

NITIN SIR CLASSES
STARING 4TH OCT 2025

आधार बैच (Aadhaar Batch)

- DURATION : 2 YEARS
- DAILY CLASSES : 2 (90 MIN EACH)
- BOOKS – PT ORIENTED PYQ'S + MAINS
- MAGZINE : HARD + SOFT COPY
- NCERT FOUNDATION
- SEPERATE PT & MAINS QUESTION SOLVING CLASSES
- TEST SERIES WITH DISCUSSION
- MENTORSHIP (PERSONALISED)
- BILINGUAL CLASSES & DOUBT SESSIONS
- MAINS ANSWER WRITING CLASSES

ONE TIME PAYMENT
RS 50,000/-
PAY IN 2 EASY INSTALMENTS
RS 55,000/-

Register Now https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR) 99991 54587

NITIN SIR CLASSES

STARING 4TH OCT 2025

सफलता बैच (Pre 2 Interview)

- DURATION : 1 YEAR
- DAILY CLASSES : 2 (90 MIN EACH)
- BOOKS - (PT + MAINS) WITH PYQ'S
- MAGZINE : HARD + SOFT COPY
- TEST SERIES WITH DISCUSSION
- DAILY THE HINDU ANALYSIS
- MENTORSHIP (PERSONALISED)
- BILINGUAL CLASSES
- DOUBT SESSIONS
- MAINS ANSWER WRITING CLASSES (WEEKLY)

ONE TIME PAYMENT
RS 30,000/-

PAY IN 2 EASY INSTALMENTS
RS 35,000/-

Register Now https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR) 99991 54587

दैनिक समाचार विश्लेषण

Follow More

- **Phone Number : - 9999154587**
- **Website : - https://nitinsirclasses.com/**
- **Email : - k.nitinca@gmail.com**
- **Youtube : -https://youtube.com/@nitinsirclasses8314?si=a7Wf6zaTC5Px08Nf**
- **Instagram :- https://www.instagram.com/k.nitinca?igsh=MTVxeXgxNGJyajN3aw==**
- **Facebook : - https://www.facebook.com/share/19JbpGvTgM/?mibextid=qi2Omg**
- **Telegram : - https://t.me/+ebUFssPR83NhNmJl**